

## सामान्य समीक्षा

### घटनाक्रमों की समीक्षा

#### (क) बृहद्-आर्थिक समीक्षा

संवृद्धि, मुद्रास्फीति तथा भुगतान संतुलन के अर्थ में अर्थव्यवस्था समुत्थानशील प्रतीत होती है, एक ऐसा संयोजन जिसमें सतत् बृहद्-आर्थिक स्थिरता के साथ संवृद्धि के संवेग के समेकन के लिए काफी गुंजायश है। सूखाग्रस्त विगत वर्ष से 9.1 प्रतिशत के सशक्त कृषिय सुधार द्वारा उत्प्लावित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2003-04 में 8.1 प्रतिशत\* की वृद्धि होने का अनुमान है। विगत में केवल तीन वर्षों में 8 प्रतिशत से उच्चतर वृद्धि प्राप्त हुई है; 1967-68 (8.1 प्रतिशत), 1975-76 (9.0 प्रतिशत) तथा 1988-89 (10.5 प्रतिशत)। तथापि ऊपर उल्लिखित अन्य तीन वर्षों की भांति 2003-04 में प्रत्याशित से उच्चतर संवृद्धि प्रतिकूल मानसून तथा कृषिय उत्पादन में गिरावट के कारण निम्न संवृद्धि (4.0 प्रतिशत) वाले वर्ष के पश्चात हुई थी। प्रमुख बृहद् सकल आंकड़े सारणी 1.1 तथा चित्र 1.1 में दिए गए हैं।

1.2 कृषि के अलावा, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों ने भी संवेग बनाए रखा जो स.घ.उ. संवृद्धि का 2002-03 में क्रमशः 6.4 तथा 7.1 प्रतिशत से त्वरित होकर 2002-03 तथा 2003-04 में क्रमशः 6.5 प्रतिशत तथा 8.4 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.2)। 2003-04 की दूसरी से तीसरी तिमाही में संवृद्धि में एक व्यापकाधारित त्वरण खनन एवं उत्खनन; विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति; व्यापार, होटल, संवहन तथा संचार; एवं निधियन, बीमा, स्थावर सम्पदा तथा कारोबार सेवाओं में भी अवलोकित हुआ।

1.3 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी त्रैमासिक स.घ.उ. आंकड़े 2003-04 की प्रथम तीन तिमाहियों में क्रमशः 5.7 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत तथा 10.4 प्रतिशत की सं.घ.उ.

संवृद्धि दरें निर्दिष्ट करते हैं। 2003-04 की तीसरी तिमाही में 10.4 प्रतिशत की सं.घ.उ. संवृद्धि दर कम से कम 1997-98, जब केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने त्रैमासिक अनुमान संकलित करने आरम्भ किए, के बाद से किसी तिमाही की सर्वोच्च वृद्धि दर थी तथा यह कृषि, वानिकी तथा मत्स्य उद्योग में 16.9 प्रतिशत, उद्योग में 6.5 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रों में 9.0 प्रतिशत की संवृद्धि द्वारा समर्थित थी।

1.4 एक हितकर विश्व आर्थिक माहौल ने 2003-04 में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत निष्पादन के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि प्रदान की। विश्व उत्पादन संवृद्धि के 2002 में 3.0 प्रतिशत से त्वरित होकर 2003 में 3.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमरीका, चीन तथा रूस द्वारा सशक्त निष्पादन तथा जापान में एक सशक्त प्रत्यावर्तन ने 2003 में विश्व आर्थिक दृष्टिकोण को उज्ज्वल बनाने में सहायता की। माल तथा सेवाओं में विश्व व्यापार की प्रमात्रा में भी विगत वर्ष में केवल 3.1 प्रतिशत की तुलना में 4.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। भारत तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सशक्त निष्पादन ने भी विश्व अर्थव्यवस्था के अच्छे निष्पादन में योगदान दिया।

1.5 मौसम विज्ञान विभाग ने चालू वर्ष के लिए सामान्य वर्षा-दीर्घावधि औसत का 100 प्रतिशत-होने की भविष्यवाणी की है। पूर्व-मानसून वर्षा (1 मार्च से मई, 2004 के अंत तक), जिसके सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है, खरीफ की बुआई के लिए अत्यंत अनुकूल है। उद्योग, जो सामान्यतः एक अच्छे कृषिय वर्ष के प्रति अनुक्रियात्मक होता है, द्वारा भी सेवा क्षेत्रक, जो 2001-02 से उत्प्लावक रहा है, सहित अच्छा निष्पादन करने की सम्भावना है। 2004-05 के लिए स.घ.उ. संवृद्धि के सांस्थानिक अनुमान 6.0 से 7.4 प्रतिशत के बीच भिन्न हैं।

\*वर्ष 2003-04 के लिए स.घ.उ. (चालू बाजार मूल्यों पर 27,55,034 करोड़ रुपए) के साथ-साथ 8.1 प्रतिशत पर इसकी संवृद्धि दर (सतत् मूल्यों पर उपादान लागत पर) 9 फरवरी, 2004 को सीएसओ द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों पर आधारित है। जब समीक्षा मुद्रण के लिए भेजी जा रही थी, सीएसओ ने वर्ष 2003-04 के लिए संशोधित अनुमान जारी किए। संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2003-04 के लिए चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. 2,72,194 करोड़ रुपए है तथा सतत् मूल्यों पर उपादान लागत पर स.घ.उ. की संवृद्धि 8.2 प्रतिशत है।

सारणी 1.1 : मुख्य संकेतक

मद	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन			
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
<b>सकल राष्ट्रीय उत्पाद (उपादान लागत पर)</b> (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	1885.7	2078.9	2230.3क्यू	2497.7	8.0	10.2 पी	7.3क्यू	12.0 ए
1993-94 की कीमतों पर	1187.0	1259.8	1306.8क्यू	1413.0	4.4	6.1 पी	3.7क्यू	8.1 ए
<b>सकल घरेलू उत्पाद (उपादान लागत पर)</b> (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	1903.0	2091.0	2249.5क्यू	2516.9	8.0	9.9 पी	7.6क्यू	11.9 ए
1993-94 की कीमतों पर	1198.6	1267.8	1318.3क्यू	1424.5	4.4	5.8 पी	4.0क्यू	8.1 ए
<b>कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रक</b> (हजार करोड़ रुपए) (1993-94 की कीमतों पर)								
कृषि उत्पादन का सूचकांक (1)	165.7	178.3	150.5 पी	179.6 P	-6.3	7.6	-15.6	19.3 पी
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	196.8	212.9	174.2 पी	210.8 P	-6.2	8.2	-18.2	21.0 पी
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक(2)	162.6	167.0	176.6	188.7	5.0	2.7	5.7	6.9
<b>उत्पन्न बिजली</b> (बिलियन के.डब्ल्यू.एच.)								
थोक मूल्य सूचकांक (3)	159.2	161.8	172.3	180.3	5.5	1.6	6.5	4.6
<b>औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (4)</b>								
मुद्रा आपूर्ति (एम 3)(5) (हजार करोड़ रुपए)	1,313.2	1,498.4	1719. 2	2000.3	16.8	14.1	14.7	16.4
<b>वर्तमान कीमतों पर आयात</b> (करोड़ रुपए)								
(मिलियन अमरीकी डालर)	2,30,873	2,45,200	2,97,206	3,46,474	7.3	6.2	21.2	16.6
<b>वर्तमान कीमतों पर निर्यात</b> (करोड़ रुपए)								
(मिलियन अमरीकी डालर)	44,560	43,827	52,719	61,718	21.0	-1.6	20.3	17.1
<b>विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (6)</b> (करोड़ रुपए)								
(मिलियन अमरीकी डालर)	1,84,482	2,49,118	3,41,476	4,66,215	20.6	35.0	37.1	36.5
<b>विनिमय दर</b> (रुपए/अमरीकी डालर) (7)								
	45.68	47.69	48.40	45.95	-5.1	-4.2	-1.47	5.33

टिप्पणी : सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपादान लागत के अनुसार हैं (नई शृंखला आधार वर्ष 1993-94)

क्यू-त्वरित अनुमान ए.-अग्रिम अनुमान पी-अनन्तिम

1. कृषि उत्पादन का सूचकांक (46 फसलों का, रोपण फसलों सहित) आधार 1981-82 को समाप्त त्रय वर्ष = 100 (संशोधित)
2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, (आधार 1993-94 = 100)
3. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1993-94 = 100)
4. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1982 = 100)
5. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।
6. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।
7. प्रतिशत परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की मूल्यवर्धन दर (+)/ह्रास (-) को निर्दिष्ट करता है।

सारणी 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रक वास्तविक वृद्धि दरें (उपादान लागत पर)

संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत							
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (पी)	2002-2003 (क्यू.)	2003-2004 (ए)
I. कृषि एवं संबद्ध उद्योग	9.6	-2.4	6.2	0.3	-0.1	6.5	-5.2	9.1
II. उद्योग	7.1	4.3	3.7	4.8	6.5	3.4	6.4	6.5
1. खनन तथा उत्खनन	0.5	9.8	2.8	3.3	2.4	2.2	8.8	4.0
2. विनिर्माण	9.7	1.5	2.7	4.0	7.4	3.6	6.2	7.1
3. बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	5.4	7.9	7.0	5.2	4.3	3.6	3.8	5.4
4. निर्माण	2.1	10.2	6.2	8.0	6.7	3.1	7.3	6.0
III. सेवाएं	7.2	9.8	8.4	10.1	5.5	6.8	7.1	8.4
5. व्यापार, होटल, संवहन तथा संचार	7.8	7.8	7.7	8.5	6.8	8.7	7.0	10.9
6. वित्तीय सेवाएं	7.0	11.6	7.4	10.6	3.5	4.5	8.8	6.4
7. सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	6.3	11.7	10.4	12.2	5.2	5.6	5.8	5.9
IV. उपादान लागत पर कुल स.घ.उ.	7.8	4.8	6.5	6.1	4.4	5.8	4.0	8.1

ए : अग्रिम अनुमान    क्यू : त्वरित अनुमान;    पी : अनन्तिम अनुमान  
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

1.6 2003-04 में संवृद्धि सुधार के साथ मूल्यों की सापेक्ष स्थिरता का सतत् अनुरक्षण किया गया। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा यथामापित मुद्रास्फीति मार्चान्त, 2003 की तुलना में मार्चान्त, 2004 में 4.6 प्रतिशत तथा औसतन 5.5 प्रतिशत थी। विनिर्माणकारी क्षेत्रक मुद्रास्फीति के लगभग 8 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी प्रमुख अंशदाता था। विनिर्माणकारी क्षेत्रक में, प्रमुख प्रवर्तक चीनी, खाद्य तेल, वस्त्र, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, बुनियादी धातु एवं मिश्रधातु तथा लोहा एवं इस्पात थे।

1.7 ऊर्जा तथा प्राथमिक उत्पाद कीमतों के सुदृढीकरण के परिणामस्वरूप जनवरी 2004 में मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत को पार कर गई। तथापि, मार्च 2004 में मुद्रास्फीति दर में पर्याप्त कमी आई। 2003-04 की अधिकांश अवधि में उच्च बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति तथा मार्च 2004 में इसकी तीव्र गिरावट अंशतः 2002-03 की अंतिम तिमाही, विशेषतया मार्च 2003 में होने वाली मूल्य वृद्धि के अग्रनयन के कारण थी। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा यथा मापित खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2003 में 5.1 प्रतिशत के चरम स्तर पर पहुंच गई जिसके पश्चात् गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हुई तथा मार्च 2004 में यह 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अप्रैल 2003 में 5.1 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2004 में और कम होकर 2.2 प्रतिशत हो गई, तथा प्रचुर खाद्यान्न

भंडारों ने खाद्य कीमतों में स्थिरता को बनाए रखने में सहायता की।

1.8 5 जून 2004 को समाप्त सप्ताह में बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति (थोक मूल्य सूचकांक) 5.5 प्रतिशत थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2004-05 के लिए अपने वार्षिक नीति विवरण में 2004-05 के लिए बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर 5 प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति निर्धारित की है। एक दीर्घ विवृति के पश्चात् मोटर स्प्रीट, उच्च गति डीजल तथा एलपीजी की कीमतों में 15 जून 2004 को ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया। कच्चे तेल का उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्य-उदाहरणार्थ 11 जून 2004 को लगभग 36 अमरीकी डालर प्रति बैरल (ब्रेंट क्रूड)-तथा बाजार घटनाक्रमों के अनुरूप एलपीजी एवं केरोसिन तथा साथ ही मोटर स्प्रीट तथा उच्च गति डीजल की कीमतों में संशोधन ऊर्ध्वमुखी दबाव डालेंगे।

1.9 मुख्यतः बढ़ते अमरीकी घाटों के कारण अमरीकी डालर के कमजोर होने से रुपया-डालर विनिमय दर प्रभावित हुई है। भारतीय रुपया, जो जून 2002 में सुदृढ होना शुरू हुआ था, में मार्च 2004 तक मासिक औसत आधार पर अमरीकी डालर के प्रति 8.8 प्रतिशत का वर्धन हुआ था। वार्षिक औसत आधार पर रुपए में अमरीकी डालर की तुलना में 2002-03 में 1.5 प्रतिशत का मूल्यहास होने के पश्चात् 2003-04 में 5.3 प्रतिशत का मूल्यवर्धन हुआ। रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव अनावश्यक समायोजन लागतों से रहित सहज तथा सुव्यवस्थित थे। इसके अतिरिक्त, जबकि

2003-04 में अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का मूल्यवर्धन हुआ, प्रमुख डालर-भिन्न व्यापार भागीदारों की मुद्राओं की तुलना में इसमें ह्रास हुआ। मुद्रास्फीति परिवर्ती को देखे हुए, व्यापार भारित प्रभावी अर्थ में मूल्यवर्धन कम सुस्पष्ट रहा जब 2003-04 में वार्षिक आधार पर रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आधार वर्ष 1993-94 के साथ 5 देशों का सूचकांक) में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.10 हाल ही के वर्षों में सुदृढ़ भुगतान संतुलन स्थिति के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडारों में सुस्थिर संचयन हुआ है। 2002-03 में 21.3 बिलियन अमरीकी डालर की सशक्त वृद्धि के पश्चात्, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों (स्वर्ण, एसडीआर एवं आईएमएफ प्रारक्षित भंडारों सहित) में 2003-04 में 36.9 बिलियन अमरीकी डालर की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 19 दिसम्बर, 2003 को प्रारक्षित भंडारों का स्तर 100 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर को पार कर गया तथा 31 मई, 2004 की स्थिति के अनुसार यह 119.3 बिलियन अमरीकी डालर था। प्रारक्षित भंडारों में यह अभिवृद्धि न केवल पूंजी अंतर्वाहों तथा वर्तमान लेखा अधिशेष पर आरोप्य है अपितु अमरीकी डालर के प्रति प्रमुख अमरीकी डालर भिन्न वैश्विक मुद्राओं (विशेषतः यूरो तथा पाउंड स्टर्लिंग) के सुस्थिर मूल्यवर्धन से प्रत्युत्पन्न मूल्यांकन लाभों के कारण भी है।

1.11 इस प्रकार, 2003-04 में मौद्रिक नीति का संकेन्द्रण प्रारक्षित भंडारों में इस प्रोत्कर्ष के संबंध में कार्रवाई करने पर था। भारतीय रिज़र्व बैंक को नकदी समायोजन सुविधा के माध्यम से रिपो प्रचालनों तथा सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार बिक्री के जरिए इन अंतर्वाहों (घरेलू मुद्रा अर्थ में 124,169 करोड़ रुपए) के प्रभाव को संतुलित करना था। इसके अतिरिक्त, बहिर्गामी विदेशी निवेश नीतियों को उदार बनाया गया तथा विभिन्न अनिवासी जमा योजनाओं पर लिबोर के ब्याज फौलावों को कम किया गया।

1.12 भुगतान संतुलन का चालू लेखा 2001-02 से अतिशेष में है। आयातों में सशक्त संवृद्धि द्वारा संवेग प्राप्त कर आर्थिक गतिविधि में संवर्धन प्रदर्शित करते हुए विगत छः क्रमिक तिमाहियों से अतिशेष वाला चालू खाता अधिशेष 2003-04 की प्रथम तिमाही में घाटे में परिवर्तित हो गया। किन्तु अनुवर्ती महीनों में यह रूझान शीघ्र ही प्रतिवर्तित हो गया जब चालू खाते ने 2003-04 के प्रथम नौ महीने में 3.2 बिलियन अमरीकी डालर का अतिशेष दर्ज किया। हालांकि व्यापार घाटा 2002-03 के सम्पूर्ण वर्ष में 12.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर 2003 में 15.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, फिर भी अप्रैल-दिसम्बर, 2003 में अपेक्षाकृत उच्च 'अदृश्य' अतिशेषों द्वारा घाटा निष्प्रभावी हो

गया। अन्य बातों के साथ-साथ साफ्टवेयर सेवा निर्यातों से अपेक्षाकृत उच्च अंतर्वाहों तथा निजी अंतरणों के उत्प्लावक अंतर्वाहों ने अदृश्य अतिशेषों को इस उत्प्लावकता में योगदान दिया। निर्यातों में 2002-03 में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003-04 में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि (अमरीकी डालर मूल्य में, सीमाशुल्क आधार) से पण्य निर्यातों का वृद्धि संवेग भी अधिकांशतः बनाए रखा गया। पण्य आयातों में संवृद्धि और भी अधिक तीव्र थी जो 2002-03 में 19.4 प्रतिशत से बढ़ कर 2003-04 में 22.8 प्रतिशत हो गई।

1.13 पूंजी खाता अतिशेष, जो 2001-02 में 11.0 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 2002-03 में 12.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था, के मुख्य अंशदाता बैंकिंग पूंजी अंतर्वाह, विदेशी निवेश तथा 'अन्य पूंजी अंतर्वाह' थे। इसी प्रकार, 2003-04 (अप्रैल-दिसम्बर) में अतिशेष विदेशी सहायता द्वारा विदेश ऋण के पूर्व भुगतान के कारण निवल बहिर्प्रवाह दर्ज करते हुए ऋण भिन्न सृजक अंतर्वाहों में निरंतर सुस्थिर वृद्धि का परिणाम था। विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत बहिर्प्रवाह भी अक्टूबर 2003 में भारतीय रिजर्व बैंक बांडों के मोचन के कारण अपेक्षाकृत उच्च थे। अप्रैल-दिसम्बर, 2003 में 10.1 बिलियन अमरीकी डालर पर अनुमानित विदेशी निवेश अंतर्वाह (निवल) में प्रोत्कर्ष मुख्यतया विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश अंतर्वाहों में तीव्र वृद्धि के कारण था। विदेशी संस्थागत निवेश में तीव्र सुधार परिलक्षित हुआ जो 2002-03 में 0.3 बिलियन अमरीकी डालर से सुधार कर अप्रैल-दिसम्बर, 2003 में 7.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सेबी के अनुसार, 2003-04 के पूर्ण वर्ष में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की राशि 10 बिलियन अमरीकी डालर थी जिसमें से दो-तिहाई निवेश वर्ष के उत्तरार्ध में किया गया। 1992 से भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों के संचयी निवेश, जो लगभग 27 बिलियन अमरीकी डालर था, के मद्देनजर अंतर्वाह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1.14 प्रारक्षित धनराशि की वृद्धि 2002-03 में 9.2 प्रतिशत से लगभग दुगुनी होकर 2003-04 में 18.3 प्रतिशत हो गई जो पूर्णतया भा.रि. बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि द्वारा चालित थी। 2003-04 में प्रारक्षित धनराशि वृद्धि हाल के वर्षों में सर्वोच्च थी। सरकार का निवल भा.रि. बैंक ऋण विदेशी अंतर्वाहों को निष्फल करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार बिक्री के कारण ऋणात्मक बना रहना जारी रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों के ह्रासमान स्टॉक ने इन प्रचालनों के कार्यक्षेत्र को कुछ कुछ बाधित किया। स्थूल मुद्रा (एम<sub>3</sub>) में 2003-04 में वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति में उल्लिखित 14.0 प्रतिशत

की लक्षित वृद्धि से 16.4 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि हुई जो वर्ष के दौरान हासिल की गई प्रत्याशित से उच्चतर स.घ.उ. संवृद्धि को प्रतिबिम्बित करती है।

1.15 मुद्रा गुणक—जो प्रारक्षित धनराशि के प्रति एम<sub>3</sub> का अनुपात है—2001-02 में 4.43 से बढ़कर 2002-03 में 4.66 होने के पश्चात् 2003-04 में घट कर 4.58 हो गया जो एम<sub>3</sub> में आगे और विस्तार की गुंजायश का सुझाव देता है। धन के आय वेग में यह गिरावट—वर्ष के दौरान औसत धनराशि स्टॉक के प्रति चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 2003-04 में जारी रहा। आय वेग 2001-02 में 1.62 से गिर कर 2002-03 में 1.50 तथा 2003-04 में और गिर कर 1.48 हो गया जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक मौद्रीकरण निर्दिष्ट करता है जिसमें आय की एक इकाई के उत्पादन में लेन देनों के लिए वस्तु विनियम का कम तथा एम<sub>3</sub> का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है।

1.16 हाल ही के वर्षों की भांति बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदीकरण जारी रहा तथा संवृद्धि में समुत्थान से 2003-04 में क्रेडिट में वृद्धि हुई। कुल बैंक क्रेडिट (खाद्य तथा खाद्य भिन्न) में विगत वर्ष में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् 2003-04 में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्य क्रेडिट, जो 1999-2000 तथा 2000-01 में त्वरित होने के पश्चात् 2002-03 में 8.3 प्रतिशत ह्रासित हो गया था, में 2003-04 में 27.3 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई जो खाद्यान्नों की अपेक्षाकृत निम्न अधिप्राप्ति तथा उच्चतर उठान के कारण थी। खाद्य भिन्न क्रेडिट का प्रवाह, जो प्रथम दो तिमाहियों में अवमंदित रहा, 2003-04 की तीसरी तिमाही से सुधरना शुरू हो गया, 2003-04 की पिछली दो तिमाहियों में खाद्य भिन्न क्रेडिट का उठान 1,01,407 करोड़ रुपए की राशि का था जो विगत वर्ष की सदृश तिमाहियों में 71,980 करोड़ रुपए की तुलना में कहीं अधिक है। सम्पूर्ण वर्ष के लिए समग्र रूप में खाद्य-भिन्न क्रेडिट में 2002-03 में 18.6 प्रतिशत (विलयन को घटा कर) की संवृद्धि की तुलना में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.17 2003-04 में, सभी उधारदाता संस्थाओं से कृषिय ऋण का कुल प्रवाह लगभग 80,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या मार्चांत 1999 में 6.1 लाख से बढ़कर मार्चांत 2004 में 413.79 लाख रुपए हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों को क्रेडिट परिदाय के सुदृढीकरण के लिए, ग्रामीण गरीबों के स्व सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने की एक प्रायोगिक परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम की एक अद्वितीय विशिष्टता राजसहायता की अनुपस्थिति है। मार्च 2004 तक, 10.8 लाख स्व सहायता

समूहों को बैंकों से जोड़ा जा चुका था जिनमें से 90 प्रतिशत का निर्माण अन्योन्य रूप में महिलाओं द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में भाग लेने वाले 504 बैंकों की 30,000 से अधिक शाखाओं द्वारा विस्तारित संचयी सहायता 31, मार्च 2004 तक 3905 करोड़ रुपए की थी। वर्ष 2002-03 में 2.56 लाख नए स्वसहायता समूहों की तुलना में वर्ष 2003-04 में 3.62 लाख नए स्व सहायता समूहों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए गए।

1.18 ब्याज दरों में अधोगामी प्रवृत्ति 2003-04 में जारी रही। भा. रि. बैंक ने 29 अप्रैल, 2003 को कार्य बंद होने के समय से बैंक दर 6.25 प्रतिशत से घटाकर 6.00 प्रतिशत कर दी। साथ ही, नकद प्रारक्षित राशि अनुपात 25 आधार बिंदु घटाकर जून 2003 में 4.50 प्रतिशत कर दिया गया। उधार दरें स्थिर रही हैं तथा उनमें जमा दरों जितनी गिरावट नहीं आई है। परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज विस्तार में हाल ही के वर्षों में वृद्धि परिलक्षित हुई है। भा.रि. बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी वास्तविक लागतों के आधार पर आरम्भिक प्रधान उधार दरें घोषित करने की सलाह दी है तथा इससे उदार ब्याज दर व्यवस्था सुदृढ हुई है। 2003-04 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम केन्द्र सरकार द्वारा बजटबद्ध बाजार उधारों से अपेक्षाकृत कम बाजार उधार लेना था जो नकद स्थिति में सुधार द्वारा सुकर हुआ। वर्ष 2003-04 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने राजकोष प्रचालनों तथा उच्चतर विस्तार से उच्चतर आय के कारण अपनी लाभप्रदता में सुधार किया।

1.19 निगमित ऋण पुनःसंरचना; लोक अदालतों, सिविल न्यायालयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों तथा समझौता निपटारों के माध्यम से वसूली; तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन से बैंक वसूली प्रबंधन में पर्याप्त सुधार हुआ। सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 2001-02 में 70,861 करोड़ रुपए से घट कर 2002-03 में 68,715 करोड़ रुपए हो गई जबकि निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 35,554 करोड़ रुपए से घटकर 32,764 करोड़ रुपए हो गई। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सकल अग्रिमों के प्रति सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का अनुपात 1999-00 में 12.7 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 8.8 प्रतिशत हो गया।

1.20 मार्चांत 2003 में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात 12.6 प्रतिशत था जो मार्चांत, 2002 में 11.8 प्रतिशत के स्तर से

अपेक्षाकृत उच्च है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सीआरएआर 2002-03 में 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों में से 26 बैंकों की सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक थी।

1.21 जब दोनो सिरों पर प्राप्तियों में गिरावट हुई तो स्थानिक लाभ वक्र रेखा गहरा गई। लघु अवधि दर (91 दिवसीय) मार्चान्त, 2003 में 5.63 से गिरकर मार्चान्त 2004 में 4.72 प्रतिशत हो गई। दीर्घावधि दर (10 वर्षीय) इसी अवधि के दौरान 6.52 प्रतिशत से गिरकर 5.44 प्रतिशत हो गई। यदि 4.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति मानें तो लघु अवधि में यह मोटे तौर पर वास्तविक लाभ दर का 20 आधार बिंदु और दीर्घावधि में मोटे तौर पर 90 आधार बिन्दु आती है।

1.22 इक्विटी बाजार प्रतिलाभ 2003-04 में 85 प्रतिशत था जो एशिया में दूसरे सर्वोच्च स्थान पर है। 2003-04 के प्रथमार्ध में निम्न रहने के पश्चात अच्छे कंपनी अर्जन के साथ जनवरी 2004 में सेंसेक्स 6,194 पार कर गया। 2003-04 में प्राथमिक बाजार में पुनरुज्जीवन हुआ था जिसने पिछले वर्ष में 4,070 करोड़ रुपए की तुलना में 2003-04 में 23,271 करोड़ रुपए जुटाए। द्वितीयक बाजार के संभलने और प्राथमिक बाजार के पुररुज्जीवन दोनों की विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सहायता की गई थी। सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीकरण 2002-03 में 7.2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 2003-04 में 13.8 ट्रिलियन रुपए (स.घ.उ. का 49 प्रतिशत) हो गया। स्थानिक बाजार व्यापार प्रमात्रा तीव्रता से बढ़ी जो 2002-03 में 9.3 ट्रिलियन रुपए से 2003-04 में 16 ट्रिलियन रुपए हो गई।

1.23 वर्ष 2003-04 में स्टॉक बाजार उतार-चढ़ाव अन्य एशियाई देशों की तुलना में पहले ही ऊंचा था। अप्रैल, 2004 में 1.48 बिलियन अमरीकी डालर के भारी निवल विदेशी संस्थागत निवेशक अंतर्वाहों के पश्चात् मई, 2004 में 0.8 बिलियन अमरीकी डालर के निवल विदेशी संस्थागत निवेशक बहिर्प्रवाह हुए थे। यह अमरीका में व्याज दरों में सख्ती, चीनी मंदी और तेल के मूल्यों में और वृद्धियों द्वारा प्रेक्षित उभरते बाजारों से विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों की धनराशि के व्यापक बहिर्प्रवाह को प्रतिबिंबित करता है। शुक्रवार, 14 मई को लोक सभा के हाल के चुनाव से परे देखें तो निफ्टी 7.8 प्रतिशत गिर गया। सोमवार, 17 मई को जब बाजार पुनः खुला तो सूचकांक 10 प्रतिशत गिर गया जिससे व्यापार एक घंटे के लिए निलंबित करना पड़ा। व्यापार पुनः शुरू होने पर सूचकांक और 5 प्रतिशत गिर गया तथा व्यापार दो घंटे के लिए निलंबित करना पड़ा। अपने निम्नतम अंक पर निफ्टी

17.5 प्रतिशत नीचे था। इसके तत्काल बाद बाजार पुनर्जीवित हुआ। जोखिम प्रबंधन प्रणाली ने अत्यंत चंचल स्टॉक मूल्यों द्वारा लागू कठोर परीक्षा का डटकर मुकाबला किया। वर्तमान सूचकांक (17 जून) 2003 के सितंबर के अंत की तुलना में अधिक है।

1.24 केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा, जो नब्बे के दशक के शुरू में घट रहा था, वह 2002-03 के संशोधित अनुमान में तत्पश्चात् बिगड़ कर 9.4 प्रतिशत के सुधार-पूर्व के स्तर से ऊंचा होकर 10.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। राजस्व घाटे ने राजकोषीय घाटे की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट दिखाते हुए अधिक व्यवधानकारी प्रवृत्ति अपनाई। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में संयुक्त राजस्व घाटा 1990-91 में 4.2 प्रतिशत से गिरकर 1996-97 में 3.6 प्रतिशत होने के पश्चात्, 2001-02 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गया तथा 2002-03 (सं.अ.) में पुनः गिरकर 6.7 प्रतिशत हो गया तथा और गिरकर 2003-04 के बजट अनुमान में 5.8 प्रतिशत हो गया। 2003-04 में संयुक्त राजकोषीय घाटे के 2,59,265 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था की गई थी जो स.घ.उ. का 9.4 प्रतिशत बैठता है। इससे भी बढ़कर कुल व्यय में पूंजी व्यय (ऋणों को छोड़कर) का गिरता हुआ हिस्सा जो 1990-91 में 13.5 प्रतिशत से 2001-02 में 10.3 प्रतिशत हो गया, घाटे की बिगड़ती हुई गुणवत्ता दर्शाता है। पूंजी व्यय को निरंतर बढ़ाने के प्रयासों के साथ इसका भाग तत्पश्चात् सुधरकर 2002-03 में 11.8 प्रतिशत हो गया। इसके 2003-04 में बढ़कर 14.5 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

1.25 केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2002-03 में स.घ.उ. के 5.3 प्रतिशत की 1,31,306 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 2003-04 में स.घ.उ. के 5.6 प्रतिशत (1,53,637 करोड़ रुपए) होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। राजकोषीय घाटे की पिछले वर्ष में स.घ.उ. के 4.4 प्रतिशत की तुलना में स.घ.उ. के 4.1 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। राजस्व घाटे में इस कमी की बजटीय व्यवस्था राजस्व प्राप्तियों में बेहतर अभिवृद्धि और राजस्व व्यय में कम वृद्धि से की गई थी। अनांकेक्षित आंकड़ों के अनुसार इस स्थिति में स.घ.उ. के अनुपात के रूप में राजकोषीय व राजस्व घाटों का 2003-04 में 4.6 प्रतिशत व 3.6 प्रतिशत होना अनुमानित है।

1.26 उदार व्याज दर की व्यवस्था से लाभ उठाने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए 2002-03 से राज्यों व केंद्र के बीच पारस्परिक सहमति से एक ऋण अदला-बदली योजना

प्रचालन में है। राज्यों को 13 प्रतिशत से अधिक की कूपन दर वाले केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों की निवृत्ति की अनुमति दी गई है। उच्च लागत वाले ऋणों की निवृत्ति का निधिपोषण अतिरिक्त बाजार उधारों तथा लघु बचत संग्रहणों की एक विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के माध्यम से किया जाता है। राज्यों को दिए गए 13,719 करोड़ रुपए और 44,565 करोड़ रुपए के उच्च लागत के केन्द्रीय ऋणों को क्रमशः 2002-03 व 2003-04 में निवृत्त किया गया था। 2004-05 में समाप्त तीन वर्ष की अवधि में 13 प्रतिशत व उससे अधिक की कूपन दर वाले सभी केन्द्रीय ऋणों की अदला-बदली की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को ब्याज संदायों में भारी बचत होगी।

1.27 वर्ष 2003-04 के बजट में आधारभूत ढांचे मुख्यतया सड़कों, रेलवे, हवाई पत्तनों व समुद्री पत्तनों को नवीन निधि-पोषण तंत्रों के माध्यम से प्रमुख बल देने की व्यवस्था शुरू की गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए अनुमानित थी। इस योजना में तीन संवेदी संघटकों-भौतिक अर्थों में सार्वजनिक निधियां तभी जारी करना जब परियोजना का पूरा होना विशिष्ट और सुपरिभाषित उपलब्धियों से जुड़ा हो; निजी प्रवर्तकों और वित्तदाताओं के साथ जोखिमों की साझेदारी हो; और किसी भी चरण में असीमित अवधि वाली सरकारी गारंटियां न हों, के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी के मार्फत सार्वजनिक निधियां जुटाना आरम्भ किया गया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 622 कि.मी. के राजमार्ग के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं तथा 1510 कि.मी. के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। मुम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों की पुनर्संरचना कार्यान्वयनाधीन है। कोचीन बंदरगाह के आधुनिकीकरण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। रेल विकास निगम लि. के लिए (आरवीएनएल) 61 परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है।

1.28 कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, सामाजिक कल्याण, पोषाहार और ग्रामीण विकास सहित) में केन्द्र का संयुक्त आयोजना व आयोजना-भिन्न व्यय 1997-98 में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 11.0 प्रतिशत हो गया। चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में व्यक्त सामाजिक सेवाओं पर व्यय 1997-98 में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 1.9 प्रतिशत हो गया।

1.29 तेरहवीं लोक सभा के भंग होने व चुनाव की घोषणा से पहले 3 फरवरी, 2004 को लेखानुदान की मांग करते हुए 2004-05 का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। हालांकि बजट में कोई नए कर प्रस्ताव शामिल नहीं थे—स.घ.उ. के अनुपात के रूप में राजस्व व राजकोषीय घाटों के 2004-05 में 2.9 प्रतिशत व 4.4 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था की गई थी।

1.30 केन्द्र सरकार और कुछ राज्यों, दोनों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों का अधिनियमन एक महत्वपूर्ण सुधार पहल रही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का अधिनियमन इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना रही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने और राजस्व घाटा 2007-08 तक समाप्त करने तथा उसके बाद समुचित राजस्व आधिक्य का निर्माण करने का अधिदेश दिया गया। यह अधिनियम बजट बनाने व इसके निष्पादन में बेहतर पारदर्शिता की व्यवस्था करता है और एक विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति की अवस्थिति इस विधान की एक स्वाभाविक सहवर्ती है। कुछ राज्यों ने राजकोषीय सुधारों में संस्थागत समर्थन सुदृढ़ करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान लागू किया है। इन राज्यों में कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं।

1.31 प्रमुख संस्थागत व विधायी सुधारों में 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी परिभाषित अंशदान आधार पर प्रचालित नई पेंशन प्रणाली थी। पहले चरण में यह नई प्रणाली सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर, केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशार्थियों के लिए है। हाल ही में नियंत्रण-मुक्त किए गए चीनी उद्योग की मांग-आपूर्ति के असंतुलन की समस्याओं के निदान के लिए मुक्त बिक्री निर्मुक्तियों को विनियमित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी मिलें अपने कोटे से अधिक चीनी न बेचें और न्यायालय इस निर्मुक्ति प्रणाली में हस्तक्षेप न करें। संसद ने औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक, 2003 व रूग्ण औद्योगिक कंपनी (निरसन उपबंध) विधेयक, 2001 भी पारित कर दिया है।

#### (ख) उपभोग, बचत और निवेश

1.32 वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय में 2001-02 में 47,099 करोड़ रुपए (5.7 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 2002-03 में 30,507

सारणी 1.3 : सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का संघटन

संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन									
	(वर्तमान मूल्यों पर)					(1993-94 मूल्यों पर)				
	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02पी	2002-03पी	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02पी	2002-03क्यू.
कुल अंतिम उपभोग व्यय	17.3	12.5	6.7	9.5	6.8	7.4	7.1	2.4	5.3	3.4
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	24.3	17.3	5.2	7.6	8.6	12.9	13.2	0.5	3.0	3.1
निजी अंतिम उपभोग व्यय	16.1	11.6	7.0	9.9	6.5	6.4	6.0	2.8	5.7	3.5
सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसमें से	5.0	24.8	3.7	3.8	8.9	0.7	20.8	0.7	-2.0	7.6
सकल नियत पूंजी निर्माण	13.3	12.7	8.8	9.0	11.0	8.7	9.3	4.1	4.3	9.4
वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	18.2	16.6	27.4	6.0	22.2	—	—	—	—	—
घटाइए - वस्तुओं और सेवाओं का आयात	21.9	18.2	15.2	5.1	19.7	—	—	—	—	—
क्यू : त्वरित अनुमान। पी: अनन्तिम										
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।										

करोड़ रुपए अर्थात् 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 1.3)। स.घ.उ. की तुलना में कम दर पर अभिवृद्धि का अर्थ है चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में निजी अंतिम उपभोग 2001-02 में 65.5 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 64.4 प्रतिशत हो गया। 2002-03 में निजी अंतिम उपभोग में गिरावट मुख्यतया अनाजों पर कम व्यय के कारण हुई थी जो 2001-02 में 1,58,621 करोड़ रुपए से गिरकर सूखा प्रभावित 2002-03 में 1,24,560 करोड़ रुपए हो गया और इससे खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों व तंबाकू का हिस्सा कुल उपभोग में 2.6 प्रतिशत बिंदु गिरकर 44.8 प्रतिशत हो गया। उपभोग की अन्य प्रमुख श्रेणियों में वस्त्र व जूतों का हिस्सा, सकल किराया, ईंधन व विद्युत, चिकित्सा देखभाल व स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और संचार तथा विविध सामान व सेवाओं में मामूली वृद्धि हुई है जबकि फर्नीचर, साज सामान, उपकरण व सेवाएं तथा मनोरंजन, शिक्षा व सांस्कृतिक सेवाएं 2001-02 तथा 2002-03 के बीच अपरिवर्तित रही हैं।

1.33 वर्ष 2002-03 में, सकल और निवल घरेलू बचत चालू मूल्यों पर क्रमशः 11.7 प्रतिशत और 14.2 प्रतिशत बढ़ी है। चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचत 2001-02 में 23.5 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 24.2 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.4)। निवल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में निवल घरेलू बचत 2001-02 में 15.4 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 16.2 प्रतिशत हो गई। 2002-03 में स.घ.उ. के अनुपात के रूप में घरेलू व निजी कंपनी क्षेत्रों, जो अर्थव्यवस्था में समग्र बचत

के मुख्य आधार हैं, की सकल बचत में मामूली गिरावट हुई थी। कुल घरेलू बचत में वित्तीय बचत का हिस्सा पिछले वर्ष में 49.0 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 45.5 प्रतिशत हो गया जबकि भौतिक परिसंपत्तियों में बचत का हिस्सा 51.0 प्रतिशत से बढ़कर 54.5 प्रतिशत हो गया।

1.34 वर्ष 2002-03 में समग्र बचत दर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में गिरावट के कारण हुई थी जो पिछले वर्ष स.घ.उ. के 2.7 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 1.9 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय 2001-02 में 62,704 करोड़ रुपए से गिरकर 2002-03 में 45,730 करोड़ रुपए हो गया। 2001-02 और 2002-03 के बीच विभागीय उद्यमों की बचत 1,023 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,339 करोड़ रुपए हो गई तथा गैर-विभागीय उद्यमों की बचत 75,035 करोड़ रुपए से बढ़कर 91,909 करोड़ रुपए हो गई।

1.35 सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) स्थिर मूल्यों पर 2002-03 में 7.6 प्रतिशत बढ़ गया। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में जीडीसीएफ, 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर, 2001-02 में 25.1 प्रतिशत की तुलना में 2002-03 में 25.8 प्रतिशत पर मामूली अधिक था (सारणी 1.5), जो निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण में सुधार होने से हुआ था। जीडीसीएफ के संघटकों में सकल नियत पूंजी निर्माण 2001-02 में स.घ.उ. के 23.7 प्रतिशत से सुधरकर 2002-03 में स.घ.उ. का 24.8 प्रतिशत हो गया जबकि स्टॉकों में परिवर्तन में तदनुसूची सुधार स.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत से स.घ.उ. का 0.5 प्रतिशत हो गया। सकल नियत पूंजी निर्माण



सारणी 1.4 : बचत और निवेश								
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (अ)	2002-03 (क्यू)
(वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)								
सकल घरेलू उत्पाद	25.1	23.2	23.1	21.5	24.2	23.7	23.5	24.2
a) सरकारी	2.0	1.7	1.3	-1.0	-1.0	-2.3	-2.7	-1.9
b) निजी	23.1	21.5	21.8	22.5	25.2	26.1	26.2	26.1
i) पारिवारिक	18.2	17.0	17.6	18.8	20.9	21.9	22.7	22.6
वित्तीय	8.9	10.4	9.6	10.4	10.6	10.7	11.1	10.3
वास्तविक	9.3	6.7	8.0	8.4	10.3	11.3	11.6	12.3
ii) निजी कॉर्पोरेट	4.9	4.5	4.2	3.7	4.4	4.1	3.5	3.4
सकल घरेलू निवेश*	26.9	24.5	24.6	22.6	25.3	24.4	23.1	23.3
सरकारी	7.7	7.0	6.6	6.6	6.9	6.3	5.8	5.7
निजी	18.9	14.7	16.0	14.8	16.7	16.3	16.5	17.1
जीएफसीएफ	24.4	22.8	21.7	21.5	21.8	22.0	21.9	22.5
स्टॉक में परिवर्तन	2.2	-1.0	0.9	-0.1	1.9	0.6	0.4	0.3
बचत-निवेश में अंतर@	-1.7	-1.3	-1.5	-1.1	-1.1	-0.6	0.3	0.9
सरकारी	-5.6	-5.4	-5.3	-7.6	-8.0	-8.6	-8.6	-7.5
निजी	4.2	6.8	5.8	7.7	8.5	9.7	9.7	8.9
टिप्पणी :	(i) सकल घरेलू निवेश सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) का द्योतक है।							
	(ii) आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।							
* :	भूल-चूक के लिए समायोजित							
@ :	बचत और निवेश की दरों के बीच अंतर का द्योतक है।							
जी.एफ.सी.एफ. :	सकल नियत पूंजी निर्माण							
अ :	अनन्तिम अनुमान; क्यू : त्वरित अनुमान							
स्रोत :	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन							

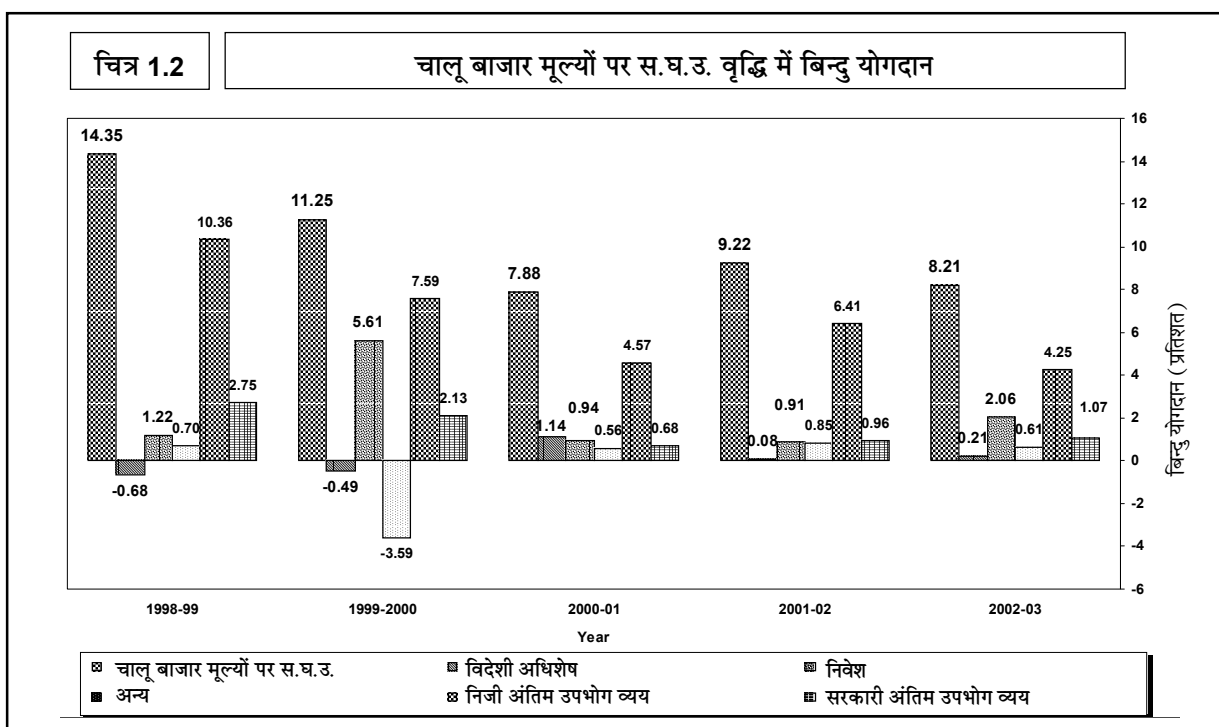
सारणी 1.5 : वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण							
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 (अ)	2002-03 (क्यू)
(बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 1993-94 मूल्य)							
जी.डी.सी.एफ.*	25.1	25.9	24.6	27.8	26.9	25.1	25.8
सरकारी	6.8	6.5	6.6	7.0	6.2	5.7	5.6
निजी	15.5	17.3	16.7	19.0	18.8	18.5	19.7
निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र	8.7	9.0	7.6	7.7	6.4	5.8	6.0
पारिवारिक क्षेत्र	6.9	8.3	9.1	11.3	12.4	12.6	13.7
जी.एफ.सी.एफ.	23.4	22.8	23.4	23.9	24.0	23.7	24.8
सरकारी	6.7	6.2	6.4	6.2	6.0	5.4	5.7
निजी	16.7	16.6	17.0	17.7	18.0	18.4	19.2
स्टॉक में परिवर्तन	-1.0	0.9	-0.1	2.0	1.1	0.4	0.5
सरकारी	0.2	0.3	0.1	0.8	0.3	0.3	-0.1
निजी	-1.2	0.7	-0.3	1.2	0.8	0.1	0.5
वृद्धि दर प्रतिशत में							
जी.डी.सी.एफ.*	-1.0	7.7	0.7	20.8	0.7	-2.0	7.6
सरकारी	-3.1	-0.8	7.3	13.3	-7.2	-3.5	2.5
निजी	-13.7	16.4	2.6	21.5	3.0	3.3	11.6
जी.एफ.सी.एफ.	1.5	2.1	8.7	9.3	4.1	4.3	9.4
सरकारी	-5.9	-2.8	9.4	2.7	0.4	-4.9	9.8
निजी	4.8	4.1	8.4	11.8	5.4	7.3	9.2
टिप्पणी :	जीडीसीएफ : सकल घरेलू पूंजी निर्माण; जीएफसीएफ : सकल नियत पूंजी निर्माण;						
	आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।						
* :	भूल-चूक के लिए समायोजित अ: अनन्तिम अनुमान; क्यू : त्वरित अनुमान						
स्रोत :	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन						

के तहत सभी क्षेत्रों में अंतर थे यद्यपि कुल मिलाकर निर्माण में निवेश की तुलना में मशीनरी में निवेश तीव्रता से बढ़ा था। सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण कार्य में नियत पूंजी निर्माण मशीनरी में 0.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में 16.7 प्रतिशत बढ़ गया। इसके विपरीत, मशीनरी में पूंजी निर्माण घरेलू क्षेत्रक में निर्माण कार्य की तुलना में तीव्रता से बढ़ा। निजी कंपनी क्षेत्र में निर्माण कार्य में नियत पूंजी निर्माण में वस्तुतः में गिरावट हुई थी।

1.36 हाल के वर्षों में घरेलू मांग संवृद्धि का मुख्य संचालक रही है (चित्र 1.2)। 2002-03 में मांग श्रेणियों में निजी अंतिम उपभोग चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. वृद्धि में 52.4 प्रतिशत के योगदान द्वारा आदि प्रवर्तक था, इसके बाद निवेश (25.6 प्रतिशत), सरकारी उपभोग (13.4 प्रतिशत) तथा विदेशी अधिशेष (2.4 प्रतिशत) का योगदान था। तथापि, संवृद्धि में निजी अंतिम उपभोग का योगदान विगत वर्ष में 69.6 प्रतिशत के मुकाबले 2002-03 में निम्नतर था। संवृद्धि में निवेश के योगदान में एकरूपता नहीं रही है, हाल के वर्षों में यह 8.4 प्रतिशत (1998-99) से 50.0 प्रतिशत (1999-2000) के बीच भिन्न थी। 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान स.घ.उ. की वृद्धि में निजी अंतिम उपभोग व्यय तथा निवेश का योगदान चालू बाजार मूल्यों पर क्रमशः 64.2 प्रतिशत एवं 21.0 प्रतिशत औसतन रहा।

1.37 चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में सकल घरेलू पूंजी निर्माण 1993-94 में 8.2 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 5.6 प्रतिशत हो गया जबकि केन्द्र सरकार के कुल व्यय उपभोग व्यय का अंश 1990-91 में 21.3 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 23.6 प्रतिशत हो गया। केन्द्र का सार्वजनिक उपभोग व्यय 2002-03 (सं.अ.) में उपांतिक रूप से गिरकर 21.2 प्रतिशत हो गया तथा 2003-04 में इसे बढ़ाकर 22.3 प्रतिशत करने की बजटीय व्यवस्था की गई। राज्यों का उपभोग व्यय 1996-97 में कुल व्यय के 38.1 प्रतिशत से बढ़कर 2000-01 में 38.8 प्रतिशत हो गया। राज्यों के उपभोग व्यय में मजदूरी तथा वेतन का अंश 1996-97 में 77.3 प्रतिशत से बढ़कर 2000-01 में 82.3 प्रतिशत हो गया।

1.38 सरकार के चालू व्यय में उपभोग व्यय तथा चालू अंतरण सम्मिलित हैं। उपभोग व्यय में वृद्धि के अतिरिक्त चालू अंतरणों में भी वृद्धि हुई जिससे सार्वजनिक निवेश कम हुआ। केन्द्र सरकार के कुल व्यय में चालू अंतरणों का अंश 1990-91 में 43.0 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 58.0 प्रतिशत हो गया तथा 2003-04 में इसे उपांतिक रूप से कम कर 56.7 प्रतिशत करने की बजटीय व्यवस्था की गई। चालू अंतरणों के घटकों में ब्याज भुगतान का अंश 1990-91 के 44.2 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 (सं.अ.) में 48.3 प्रतिशत



हो गया तथा 2003-04 में इसके 48.2 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जो 1990-91 में चालू अंतरणों का 24.6 प्रतिशत था 2002-03 (सं.अ.) में उपांतिक रूप से बढ़कर 25.0 प्रतिशत हो गया तथा 2003-04 में इसके 24.8 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई। चालू अंतरणों में राजसहायताओं का अंश 1990-91 के 23.8 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 19.6 प्रतिशत हो गया तथा 2003-04 में इसके बढ़कर 21.1 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई।

1.39 केन्द्र सरकार के उपभोग व्यय तथा अंतरण भुगतानों में वृद्धि के कारण कुल व्यय में चालू व्यय का अंश 1990-91 के 64.3 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 (सं.अ.) में 79.2 प्रतिशत हो गया तथा 2003-04 में इसके उपांतिक रूप से घटकर 79.0 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई। कुल व्यय में राज्य सरकारों के कुल व्यय का अंश 1996-97 में 81.3 प्रतिशत तथा 2000-01 में 81.3 प्रतिशत पर और भी अधिक था। राज्य सरकारों के कुल व्यय में चालू अंतरणों का अंश 1996-97 तथा 2000-01 के बीच 45.0 प्रतिशत से गिरकर 42.6 प्रतिशत हो गया।

1.40 हाल के वर्षों में ब्याज दरों को उदार बनाए जाने से निवेश संवृद्धि के लिए एक अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ है। खाद्य-भिन्न क्रेडिट के उठान में पुनरुज्जीवन के लक्षण दर्शित हुए हैं तथा ऐसे संकेत मिले हैं कि समान पूंजी स्टॉक से कार्य कुशलता वृद्धि के माध्यम से अधिक उत्पादन की गुंजाइश वर्धनात्मक रूप से सीमित होती जा रही है जिसका परिणाम नई क्षमताओं में निवेश होगा। 2003-04 के उत्तरार्द्ध में स्टॉक मूल्यांकन में सुधार तथा प्राथमिक बाजारों में गतिविधि की हलचल से निवेश दृष्टिकोण की आशावादिता पुनर्बलित हुई है। औद्योगिक विकास के संवेग में तेजी से निजी निवेश में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे औद्योगिक संवृद्धि का संवर्धन होगा तथा इस प्रकार एक सही चक्र की शुरुआत होगी।

1.41 2003-04 में समाप्त होने वाले तीन क्रमिक वर्षों के लिए भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते का अधिशेष यह इंगित करता है कि शेष विश्व ने सकल मांग को बनाए रखने में योगदान दिया है। निवेश में वृद्धि होने पर इस अधिशेष में गिरावट होने की संभावना है तथा देश उच्चतर गति से लगातार विकास के चरण की ओर पारगमन करेगा।

## (ग) उत्पादन

1.42 एक अच्छे मानसून ने 2002-03 के 174.2 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के स्तर को बढ़ाकर 2003-04 में 210.8 मिलियन टन करने में मदद की, जिसमें अन्न तथा दलहन दोनों के उत्पादन में वृद्धि का योगदान था। 2004-05 में कृषि उत्पादन की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा दिए गए सामान्य मानसून पूर्वानुमान के साथ उज्ज्वल मानी गई हैं।

1.43 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में समग्र वृद्धि 2002-03 के 5.7 प्रतिशत से सुधरकर 2003-04 में 6.9 प्रतिशत हो गई जोकि खनन में 5.1 प्रतिशत, विद्युत में 5.0 प्रतिशत तथा विनिर्माण में 7.2 प्रतिशत वृद्धि दर द्वारा समर्थित है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर औद्योगिक संवृद्धि व्यापक धारित थी। पूंजी माल 12.7 प्रतिशत की वृद्धि सहित शीर्ष पर था, जिसके पश्चात् उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं थीं जिनमें 11.6 प्रतिशत की विकास दर दर्ज हुई। खुदरा ऋणों की वर्द्धित उपलब्धता तथा निम्नतर ब्याज दर ने परवर्ती के विकास में योगदान दिया। मध्यवर्ती माल तथा मूलभूत माल ने भी क्रमशः 6.2 प्रतिशत तथा 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर सहित 2002-03 के मुकाबले 2003-04 में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि 2002-03 के 12.0 प्रतिशत से पर्याप्त रूप से घटकर 2003-04 में 5.7 प्रतिशत हो गई।

1.44 द्वि-अंकीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार 17 उद्योग समूहों में से तीन में 2003-04 में 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। इन उद्योगों में परिवहन, उपकरण तथा पुर्जे (17 प्रतिशत), कागज तथा कागज उत्पाद (15.9 प्रतिशत) तथा परिवहन उपकरण से भिन्न मशीनरी तथा उपकरण (15.2 प्रतिशत) सम्मिलित हैं। पेय पदार्थों तथा तम्बाकू तथा मूल धातुओं एवं मिश्र धातुओं में क्रमशः 9.4 प्रतिशत तथा 9.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।

1.45 2001-02 में 42 बिलियन वर्गमीटर वस्तु का चरम उत्पादन 2002-03 में उपांतिक रूप से घटकर 41.9 बिलियन वर्गमीटर हुआ। 2003-04 में पावरलूम यूनितों तथा ट्रक संचालकों की हड़ताल, रूई के मूल्यों में वृद्धि तथा वस्त्रों की अल्प मांग के कारण प्रारंभिक तीव्र गिरावट के बावजूद, इसमें पुनः तेजी आई तथा वर्ष के अंत तक 42.2 बिलियन

वर्गमीटर का उत्पादन हुआ। वस्त्रों के कुल उत्पादन में पावरलूम क्षेत्र का अंश विगत वर्ष के 80.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2003-04 में 82 प्रतिशत हो गया।

1.46 इस्पात के उत्पादन तथा निर्यात, चीन में इस्पात की प्रबल मांग तथा मज़बूत घरेलू बाजार द्वारा प्रेरित होकर बढ़ना जारी रहा। 2003-04 में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 36.2 मिलियन टन पर पहुंच गया जबकि तैयार इस्पात का निर्यात 17.6 प्रतिशत बढ़कर 5.3 मिलियन टन हो गया।

1.47 2003-04 के दौरान वाहनों के उत्पादन में विगत वर्ष के 18.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यावसायिक वाहनों में 35.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यात्री कारों में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय विनिर्माण में मुख्य घटनाक्रम वाहनों के सहायक उपकरणों एवं तैयार वाहनों के निर्यात में सफलता रही है। 2003-04 में वाहनों के निर्यात में 56 प्रतिशत की वृद्धि होने से भारत छोटे यात्री वाहनों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को एक नये खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता हुआ प्रतीत हुआ।

1.48 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 26.7 प्रतिशत के कुल सारांश वाले छः मुख्य एवं आधारभूत संरचना उद्योगों (नामत: विद्युत, कोयला, सीमेंट, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद) ने 2002-03 के 5.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के मुकाबले 2003-04 में उपांतिक रूप से 5.4 प्रतिशत की निम्न तर औसत वृद्धि दर दर्ज की। अन्य आधारभूत क्षेत्रों में नये सेलफोन कनेक्शन (159.2 प्रतिशत की वृद्धि सहित), रेलवे माल ट्रेफिक (7.5 प्रतिशत), मुख्य बंदरगाहों में संचालित कार्गो (9.9 प्रतिशत) तथा वायु पत्तनों (5.3 प्रतिशत) तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों में हवाई यात्रा ट्रेफिक (10.3 प्रतिशत) ने 2003-04 में सतत् औद्योगिक विकास तथा सेवा गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण अच्छा प्रदर्शन किया।

1.49 आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 2003-04 में की गई मुख्य पहलों में जून 2003 में विद्युत अधिनियम की अधिसूचना; केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को राज्य विद्युत बोर्ड की देयताओं के एक बारगी निपटान हेतु 28 राज्यों द्वारा त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना; मई 2003 में 50,000 मेगावाट जल विद्युत का आरम्भण, दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था; तथा राज्य

की राजधानियों को जोड़ने वाली 10,000 कि.मी. की सड़कों के विकास हेतु भारत जोड़ो परियोजना शामिल हैं।

1.50 वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियों की घोषणा की गई। मुख्य उपायों में वस्त्रों, पोशाक तथा परिधान, जिनमें निर्यात तथा रोजगार की संभावनाएं उच्च होती हैं, के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज; जैव प्रौद्योगिकी औषध विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी, के उभरते क्षेत्रों को आयकर रियायत; पर्यटन हेतु व्यय कर को वापस लेना तथा; रसायनों, चमड़ा प्लास्टिक एवं कागज उत्पादों की 75 मर्दों से लघु मान आरक्षण वापस लेना सम्मिलित है।

### (घ) रोजगार एवं गरीबी

1.51 यह भली भांति विदित है कि गरीबी का अनुपात 1993-94 के 36 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से घटकर 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत हो गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) ने गरीबी अनुपात में 2007 तक 5 प्रतिशत बिन्दु की कमी लाने तथा 2002 तक 15 प्रतिशत बिन्दु की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

1.52 तदनंतर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2000-01 (56वां दौर) तथा 2001-2002 (57वां दौर) के लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय हेतु 'विरल' सर्वेक्षण संचालित किए गए। 57वें दौर के परिणामों के अनुसार चिरकालिक भूखे परिवारों (वर्ष के किसी माह में पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं करने वाले) का अनुपात घटकर ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 0.1 प्रतिशत हो गया। मौसम विशिष्ट भूख के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार 16 परिवार तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार 3 परिवारों ने वर्ष के केवल कुछ महीनों में ही पर्याप्त भोजन प्राप्त होने की सूचना दी।

1.53 2003-04 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए जो मुख्य पहल की गई है उनमें अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को शामिल करने के लिए अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार; समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना नामक एक विशेष पेंशन नीति का प्रारंभ; प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करना; जनवरी 2004 में प्रायोगिक आधार पर 50 जिलों में असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

योजना शुरू करना; छ: पिछड़े राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरांचल) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के जैसे संस्थानों की स्थापना की पहल करना सम्मिलित हैं।

1.54 आर्थिक समीक्षा 2002-03 में सूचित किया गया था कि वर्तमान दैनिक प्रास्थिति आधार पर रोजगार वृद्धि की दर 1983-1994 में 2.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से गिर कर 1994-2000 में 1.07 प्रतिशत वर्ष हो गई, रोजगार वृद्धि में अवमंदन मुख्यतः कृषि रोजगार में लगभग प्रगतिरोध के कारण था, हालांकि सेवाओं के भीतर सभी उप-क्षेत्रकों (समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं को छोड़कर) में रोजगार वृद्धि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक थी।

1.55 रोजगार के कुछ अनुमान 1999-2000 से आगे की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। जुलाई-दिसम्बर 2002 में संचालित वार्षिक दौरों के अनुसार, देश में रोजगार वृद्धि 1994-2000 में 1.07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तुलना में सुधरकर 2000-02 में 2.07 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गई। सम्पूर्ण अर्थों में, 2000-2002 में औसतन 84 लाख प्रति वर्ष का अतिरिक्त रोजगार प्रति वर्ष एक करोड़ के अतिरिक्त रोजगार के लक्ष्य से कम रहा। भारी संदर्श संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। तथापि, ये अनुमान विरल संदर्शों पर आधारित हैं जिनमें

#### मुद्दे तथा प्राथमिकताएं

1.56 संवृद्धि प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए हाल के महीनों में निवेश माहौल में सुधार के चिन्हों को संपोषित करने की आवश्यकता है। अमरीकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलनों, विशेषतया विशाल चालू खाता तथा राजकोषीय घाटों तथा इराक में स्थिति के संबंध में चिंताएं बनी हुई हैं। किन्तु वैश्विक आर्थिक माहौल एवं दृष्टिकोण ने भारत की संवृद्धि प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक लाभप्रद पृष्ठभूमि उपलब्ध कराना जारी रखा है।

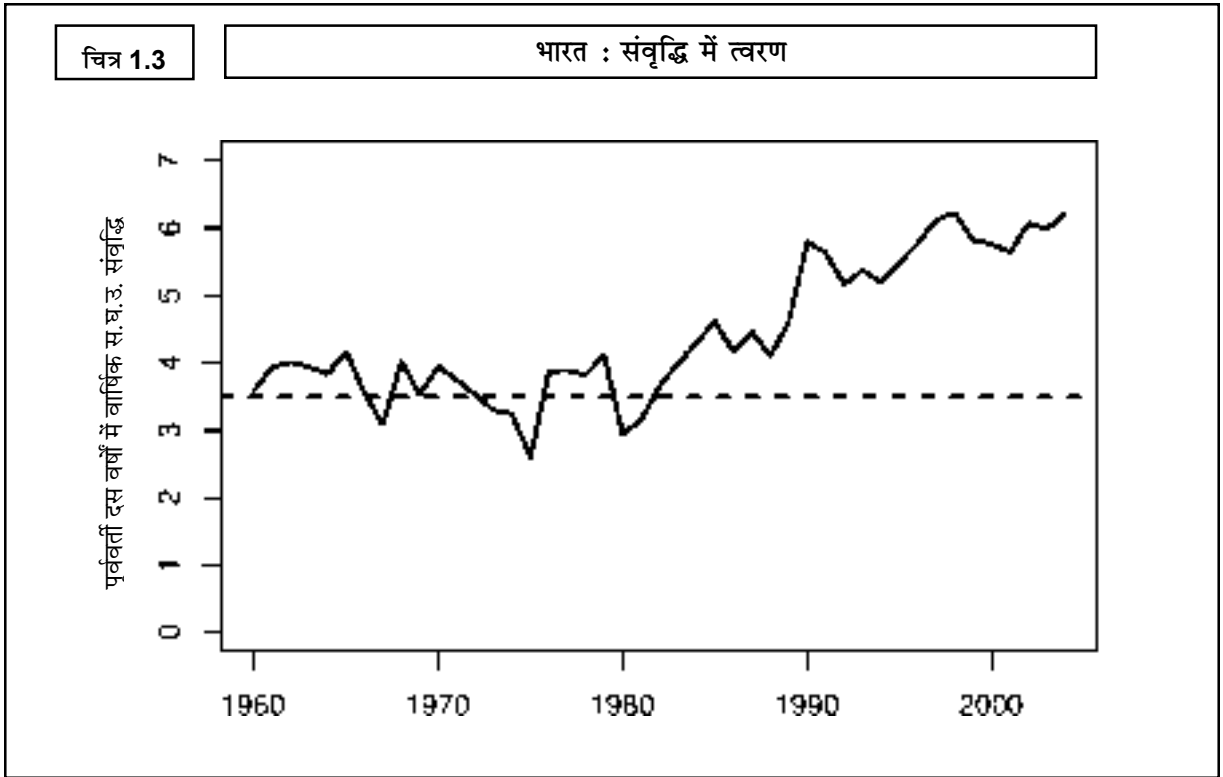
1.57 अर्थव्यवस्था के समक्ष पांच प्रमुख चुनौतियां हैं— (i) संवृद्धि संवेग को बनाए रखना तथा आगामी पांच वर्षों में 7-8 प्रतिशत की वार्षिक औसत संवृद्धि हासिल करना, (ii) वार्षिक मुद्रा स्फीति दर को मध्यक एकलांक स्तर तक नियंत्रित करना, (iii) कृषिय-प्रसंस्करण के विविधकरण तथा विकास के माध्यम से कृषिय संवृद्धि को बढ़ावा देना, (iv) कृषि में न केवल अतिशेष श्रमिकों को बल्कि प्रतिवर्ष श्रम बल में शामिल होने वाली महिलाओं एवं तरुणों की

अभूतपूर्व संख्या को एकीकृत करने के लिए उद्योग का कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक तीव्रता से विस्तार करना, (v) राजस्व वर्धन एवं व्यय प्रबंधन के जरिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रभावी करना तथा राजस्व घाटे को कम करना।

1.58 भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि, जिसमें 1979 से स्थिर त्वरण हुआ है (आकृति 1.3), को नीतियों के समुचित मिश्रण द्वारा 7-8 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। गरीबी के त्वरित उन्मूलन के लिए उच्चतर संवृद्धि आवश्यक है। जबकि भारत का औसत 5.7 प्रतिशत प्रति वर्ष का प्रभावपूर्ण 23 वर्षीय संवृद्धि रिकार्ड है, और भी बेहतर निष्पादन की संभाव्यता काफी है। पूर्व एशिया के कई देशों ने 23 वर्षों से भी अधिक अवधि तक अपेक्षाकृत तीव्र आर्थिक संवृद्धि कायम रखी (सारणी 1.6)। संयोजन के जादू से, संवृद्धि दर में छोटे अंतर भी कई दशकों में परिणामों में परिमाणान्तरक अंतर ला देते हैं। उदाहरणार्थ, 1963 में कई प्रकार से भारत की तुलना में अधिक प्रतिकूल दशाओं के होते 33 वर्षों में 8.31 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि ने कोरिया को एक विकसित देश में रूपांतरित कर दिया।

1.59 स्थायी संवृद्धि एक कुशल अवसंरचना की उपलब्धता पर टिकी है। यद्यपि दूरसंचार, सड़कों तथा पतनों जैसे क्षेत्रों में मांग-आपूर्ति अंतराल 1990 के दशक के प्रथमार्ध से संकीर्ण हो गए हैं, इन सुविधाओं, विशेषतया विश्वसनीय गुणवत्ता वाली, की अपर्याप्त उपलब्धता ने आर्थिक वृद्धि को बाधित करना जारी रखा है। विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के बावजूद अवसंरचना में निवेश अन्यंत अपर्याप्त रहा है। एक सशक्त समर्थकारी माहौल की अनुपस्थिति में, निजी क्षेत्र, अवसंरचना में सार्वजनिक व्यय में कमी की क्षति पूर्ति नहीं कर पाया है।

सारणी 1.6 : कुछ पूर्व एशियन उच्च-संवृद्धि अनुभवः (1961-1996)	
देश	स.घ.उ. संवृद्धि
हांग-कांग	7.97
इंडोनेशिया	6.39
कोरिया	7.96
मलेशिया	7.22
सिंगापुर	8.74
थाईलैंड	7.71
टिप्पणी : स.घ.उ. संवृद्धि का वार्षिक दर 1995 अमरीकी डालर	



1.60 अवसंरचना में कुछ सुधार ने हाल के संवृद्धि सुधार को सहारा दिया है। विधायी परिवर्तनों यथा बिजली अधिनियम 2003 तथा सांस्थानिक परिवर्तनों यथा एकीकृत प्रवेश सेवा लाइसेंसिंग व्यवस्था से पर्याप्त लाभांश प्राप्त हुए हैं। इन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समुचित प्रयोक्ता प्रभारों के संग्रहण, नई प्रौद्योगिकियों के दोहन, निजी क्षेत्र उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने वाले विनियामक ढांचों पर अधिक बल से लाभ उपार्जित हुए हैं। इस बल के सशक्तीकरण में ही आगे प्रगति है। यथासंभव सार्वजनिक निजी भागीदारी से, सरकारी धन के उत्तोलम के लिए, बजट 2003-2004 में घोषित नई जीवनक्षमता-अंतराल निधियन प्रक्रम को संभाव्यता को स्पष्टता परिभाषित तथा पारदर्शी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से हासिल किया जाना आवश्यक है।

1.61 सामाजिक अवसंरचना यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, न केवल उच्च संवृद्धि को बनाए रखने बल्कि कल्याणवर्धन के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी भौतिक अवसंरचना है। गरीबी की जड़ अक्सर निरक्षरता एवं बुनियादी स्वास्थ्य के अभाव में निहित होती है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर किए जा रहे सार्वजनिक खर्चों को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तथा 2-3 प्रतिशत के 2003-2004 (बजट अनुमान) स्तरों से, एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद क्रमशः

3.1 प्रतिशत तथा 1.4 प्रतिशत करने की घोषणा से सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं के निवारण में काफी सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में उच्चतर परिव्ययों के अनुरूप परिणामों का गहन अनुवीक्षण आवश्यक है। सार्वजनिक रूप से निधियन की गई बुनियादी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। एनसीएमपी में घोषित 150 अयुक्त जननक्षम जिलों में अत्यधिक लक्षित परिवार नियोजन कार्यक्रम न केवल जनसंख्या प्रबंधन में बल्कि इन जिलों में गरीबी के विस्तार को कम करने में भी काफी हद तक सफल होगा।

1.62 एनसीएमपी में एक त्वरित एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। देश में एचआईवी/एड्स के शून्य स्तर वर्धन को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रहरी साईटों के गठन तथा एचआईवी/एड्स का अनुवीक्षण करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रयोग के माध्यम बेहतर निगरानी, कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध का संवर्धन तथा औषध दुरुपयोग की रोकथाम तथा एक बारगी प्रयुक्त किए जाने वाले सिरिंजों के वितरण समाहित निर्भीक एवं समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि देश के वृहत-आर्थिक ढांचे पर एचआईवी/एड्स के संभावित प्रतिकूल प्रभावों के कारण भी आवश्यक है।

1.63 अर्थव्यवस्था ने खाद्यान्नों के भरपूर स्टॉकों, उत्पादन बाजारों में बढ़ती स्पर्धा तथा राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों के एक समुचित मिश्रण के कारण सापेक्ष रूप से निम्न मुद्रास्फीति के लाभों का उपयोग किया है। बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर, 2004 की प्रथम तिमाही में मार्चात 2004 में तीव्रता से गिरकर 4.6 प्रतिशत होने के पश्चात 5 जून, 2004 को थोड़ा सा बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई। इसका मुख्य कारण वर्ष के इस भाग के दौरान फलों तथा सब्जियों के मूल्य में मौसमी वृद्धि का होना था। कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि में तेजी संभवतः लगातार बदतर होती मुद्रास्फीति की गति की घातक नहीं है।

1.64 अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में प्रोत्कर्ष से, हाल में प्रेक्षित वृद्धि समुत्थान के अवरूद्ध होने की संभावना नहीं है। परन्तु, अगर इसे कायम रखा गया तो इससे न केवल इस प्रक्रिया के संवेग के अवमंदित होने का खतरा है बल्कि मुद्रास्फीति पर भी ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, 2003-2004 में एम3 में उच्च वृद्धि के पश्चात विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशि में बढ़ोतरी अगर जारी रही, तो इसके लिए बाह्य उदारीकरण तथा निवफलीकरण राजकोषीय लागतों को सीमित करने में बहुल लक्ष्यों के समाधान तथा विदेशी मुद्रा बाजारों तथा निम्न मुद्रास्फीति दोनों में सुव्यवस्थित दशाओं के अनुरक्षण जैसी नीतियों के दक्ष संयोजन की आवश्यकता होगी।

1.65 एक लाभप्रद क्रिया के रूप में, कृषि की पूर्ण संभाव्यता की, शीघ्र पहचान होनी चाहिए, जिससे न केवल किसान तथा ग्रामीण गरीबों के एक बड़े भाग को लाभ होगा, बल्कि इससे शेष अर्थव्यवस्था के कृषि के पश्चगामी तथा पूर्वगामी सम्पर्कों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उच्चतर पैदावार तथा अनाजों से हटकर उच्च मूल्य तथा श्रम गहन कृषि एवं संबंधित क्रियाओं से विविधीकरण 4 प्रतिशत से अधिक की सतत् वार्षिक कृषिय संवृद्धि को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पशुधन तथा मत्स्य पालन, बागवानी, जैव-कृषि, वाणिज्यिक फसलें तथा कृषिय संसाधन उच्च वृद्धि के संभावित क्षेत्र हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था का यौक्तिकीकरण तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरण उपायों की शुरूआत, ग्रामीण अवसंरचना तथा पश्च-पैदावार प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में सुधार कृषिय उत्पादों में भारतीय सामान्य बाजार के एकीकरण के लिए विधायी सुधार तथा अनुसंधान एवं विकास का सुदृढीकरण, उच्च कृषिय वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

1.66 अक्सर एमएसपी प्रक्रम, जो 24 कृषिय वस्तुओं के लिए विद्यमान है, के परिणामस्वरूप मूल्यों को पर्याप्त विकृत होने का खतरा रहता है। एमएसपी की लागत आधारित गणनाएं मांग दशाओं के अननुरूप हो सकती हैं तथा इसका परिणाम अत्यधिक संचयन या निर्यात राजसहायता होता है। कृषिय उत्पादों के निवल आयात से निवल निर्यातक की ओर संग्रमण के साथ-साथ वस्तु विनिमय में फ्युचर्स मूल्यों की उपलब्धता से, लागत आधारित एमएसपी पर पुर्नविचार की आवश्यकता है।

1.67 कृषि के पूंजी निर्माण का 1990 के प्रारंभ में सकल घरेलू उत्पाद के 1.9 प्रतिशत से गिरकर 2000-2001 के पश्चात सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत हो जाना चिन्ता का विषय है। गिरावट का यह रूझान मुख्यतः नब्बे के दशक के मध्य से कृषि में सार्वजनिक निवेश में गिरावट के कारण है। हालांकि हाल के वर्षों में इस रूझान में कुछ प्रतिवर्तन हुआ है, कृषि में विशेषतः ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई तथा कृषिय अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है।

1.68 कृषिय संवृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए किए जाने वाले कुछ उपायों के लिए एक मध्यावधिक ढांचे के विकास की आवश्यकता है। इस दौरान यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कृषि लाभप्रद अवसरों को छोड़ा न जाए और पर्याप्त क्रेडिट की कमी के कारण किसानों को हानि न पहुंचे। सत्तर के दशक से, कृषि को मिलने वाले अल्पावधिक संस्थागत क्रेडिट की दशकीय औसत एवं वृद्धि दर 15 प्रतिशत पर स्थिर हो गई है, जबकि दीर्घावधिक क्रेडिट के परिणाम की संवृद्धि दर वास्तव में 1970 के दशक के वर्षों में 20.2 प्रतिशत से गिरकर 1990 के दशक के वर्षों में 11.9 प्रतिशत हो गई है। कृषि में पूर्ण संभाव्यता को पहचानने में मदद करने वाले अन्य कारकों में, अधिक किसानों के लिए सामयिक संस्थागत क्रेडिट तक बेहतर पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1.69 18 जून, 2004 को कृषि को क्रेडिट का प्रवाह दुगुना करने के लिए सरकार ने कुछ तात्कालिक कदमों की घोषणा की है। कृषि को क्रेडिट के प्रवाह पर व्यास समिति की अनुशंसाओं की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है ताकि उनका शीघ्र क्रियान्वयन किया जा सके। क्रेडिट समस्या के समाधान के लिए दो विचारणाएं संगत हैं। पहली, एससीबी की 47,092 शाखाओं के बावजूद, जिनमें क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक तथा ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सहकारियों के एक लाख से अधिक आउटलेट शामिल हैं, एक निम्न-लागत नेटवर्क के जरिए अपर्याप्त पहुंच की समस्या बनी हुई है। औपचारिक वित्तीय संरचना सहित लघु-वित्त संस्थाओं, जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), न्यासों तथा अलाभार्थ संभाग 25 कंपनियों को एकीकृत करने के लिए विनियामक सुधार तथा एजेंट बैंकिंग की संकल्पना का विकास करना सहायक सिद्ध हो सकता है। जब अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या अपनी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक बाजारों से उच्च दर पर उधार लेती है, उनके विस्तार को औपचारिक क्षेत्र तक बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1.70 58 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है—एक ऐसा क्षेत्र जो स.घ.उ. के केवल 22 प्रतिशत का उत्पादक है। जहां कृषीय वृद्धि को त्वरित कर 4-4.5 प्रतिशत किया जाना अत्यावश्यक है, इतनी संवृद्धि से भी स.घ.उ. में कृषि का अंश और कम होने की संभावना है। अतः अतिरिक्त कृषिय श्रम को अन्य क्षेत्रों, उल्लेखनीय रूप से उद्योग में समाहित करने की आवश्यकता है। कृषीय उत्पादन केन्द्रों के निकट कृषि-संसाधन उद्योग का तीव्र विकास लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से हटाकर शहरी क्षेत्रों में लाए बिना यह बदलाव ला सकता है।

1.71 पारंपरिक रूप से, विकसित विश्व के अधिकतर भागों में, सेवा क्षेत्र से जुड़े रोजगार, उनके उत्पादन की तुलना में अधिक तीव्रता से बढ़े। भारत में मुख्यतः कुशल श्रम पर आधारित उपक्षेत्रों (जैसे सूचना प्रौद्योगिकी) में संकेन्द्रण के कारण सेवाओं में श्रमिक उत्पादकता में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप सेवाओं के क्षेत्र में नौकरियों में सापेक्ष रूप से धीमी वृद्धि हुई है। जहां पर्यटन एवं पर्यटन संबंधी सेवाओं, जैसे होटलों में रोजगार सृजन की काफी संभाव्यता है, केवल सेवा क्षेत्र द्वारा ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान उपलब्ध कराना संभव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवाएं जैसे व्यवसाय प्रक्रिया हिस्सेतण हाल के पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ रहा है, और भारत की मानव संसाधन सम्पन्नता को देखते हुए इसमें सतत वृद्धि की संभाव्यता है। तथापि इन सेवाओं के लिए कौशल अपेक्षाएं एक विशिष्टीकृत प्रकृति की होती हैं तथा कुछ विकसित देशों में कुछ अस्पष्ट संरक्षणवात्मक प्रवृत्तियों का अविर्भाव एक व्यवधानकारी रूझान है। उद्योग को न केवल अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर को

बढ़ावा देने बल्कि मौजूदा बेरोजगारों तथा साथ ही नए प्रवेशकों, जिनमें एक अनुमान के अनुसार श्रम बल में प्रतिवर्ष 1.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, के लिए लाभप्रद रोजगार का सृजन करने के लिए भी तीव्रता से बढ़ने की आवश्यकता है।

1.72 वर्ष 1995-96 से वार्षिक औद्योगिक अभिवृद्धि निराशाजनक एकल अंकों में रही है। भारतीय आर्थिक नीति के समक्ष एक संवेदनशील चुनौती औद्योगिक विकास को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से अधिक बनाए रखने के लिए योजनाएं तैयार करने में निहित है। उद्योग के कुछ उपक्षेत्रों, जैसे वाहन उद्योग ने भारतीय श्रम तथा पूंजी में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। आगे, औद्योगिक गतिविधियों की एक विविध श्रेणी में अनेक भारतीय फर्मों, जो वैश्विक उत्पादन श्रृंखला में जुड़ने तथा निर्यातों की तीव्र संवृद्धि हासिल करने में सफल हुई हैं। अनुभव यह दर्शाते हैं कि समुचित पैमाने, निवेश तथा प्रौद्योगिकी से तीव्र औद्योगिक विकास वस्तुतः संभव है। 1 जनवरी, 2005 से वस्त्र एवं कपड़ा (एटीसी) संबंधी समझौते के समापन में, वस्त्र उद्योग, जो सबसे बड़ा नियोजित उद्योग है की तीव्र वृद्धि में योगदान देने की अत्यधिक संभाव्यता है।

1.73 अवसंरचना, विशेषतः युक्तिसंगत लागत पर पर्याप्त तथा विश्वसनीय बिजली आपूर्ति तथा परिवहन सुविधाओं के अलावा निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। 2003-04 के उत्तरार्ध में खाद्य भिन्न क्रेडिट का उठान, निवेश में संभावित पुनरूज्जीवन की ओर संकेत करते हैं, जिसे संपोषित किया जाना आवश्यक है। वर्धित प्रतिस्पर्धा तथा बेहतर गैर-निष्पादनकारी सम्पत्ति आस्ति सुधार के जरिए बैंकों के उधार-दरों का जमा दरों के साथ बेहतर संरेखण पुनरूज्जीवन को सशक्त करेगा।

1.74 विदेशी निवेश, न केवल अपने साथ लाने वाली निधियों के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रौद्योगिकीय जानकारी, परिष्कृत कार्पोरेट अभिशासन पद्धतियों तथा विदेशी बाजारों तक पहुंच, जो अक्सर इससे जुड़े होते हैं, के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले तीन दशकों में प्रेक्षित चीन के औद्योगिक विकास की उपल्लावकता का पर्याप्त भाग, विदेशी निवेश के पर्याप्त अतर्वाहों का परिणाम था। 2002-03 से भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में पाई गई मंदी को प्रतिवर्तित करने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहों को बढ़ाने के



लिए विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश व्यवस्थाओं जिनमें प्रक्रियात्मक मुद्दे भी शामिल हैं, के उपयुक्त उदारीकरण पर विचार करने की आवश्यकता है।

1.75 वर्ष 2003-04 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों में प्रदर्शित सशक्त रूचि प्रोत्साहक है तथा यदि बर्हिजात कारक न हों तो इसके जारी रहने की संभावना है। विभिन्न आपूर्ति तथा मांग कारकों ने अनेक विकसित देशों में संस्थाओं के ज़रिए निवेश को एक तीव्रता से बढ़ता हुआ क्षेत्र बना दिया है। इन देशों में जनसंख्या के वयोवृद्ध होने, निधियन् की गई पेंशन प्रणालियों तथा बढ़ती संपत्ति के कारण, निवेशकों से संस्थाओं को निधि-आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। विविधताओं में सुगमता, बेहतर कार्पोरेट अभिशासन, नकदीकरण, अपविनियमन तथा राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण, संस्थाएं बेहतर सेवाएं तथा आकर्षक प्रतिलाभ देने में भी समर्थ हैं। इस पृष्ठभूमि में, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों की बड़ी तथा बढ़ती हुई मांग की संभावना है, जिसका दोहन किया जाना आवश्यक है।

1.76 उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करने वाले अन्य कारकों में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची में से शेष मदों को हटाने का मुद्दा है। लघु एवं श्रेणी के मध्यम उद्यम औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भावी व्यवसायों को संपोषित करने के लिए अवलम्बन प्रदान करते हैं। ये उपयुक्त उत्पाद अभिकल्पों तथा तकनीकों का चयन करते हैं—चाहे वो श्रम-गहन हो या पूंजी-गहन तथा उनमें तीव्र परिवर्तनशील बाजार दशाओं के प्रति प्रतिक्रिया का सुनम्य प्रबंधन सामर्थ्य है। हाल के कुछ वर्षों में प्रेषित आरक्षण नीति के क्रमिक विघटन की प्रगति जारी रहनी चाहिए और आरक्षण के ज़रिए संरक्षण की नीति को भावी नीति की आधारशिला के रूप में प्रोत्साहन से प्रतिस्थापित करना चाहिए। क्रेडिट, सेवाओं, प्रौद्योगिकीय सहायता, अवसंरचना की पर्याप्त आपूर्ति तथा निम्न लेनदेन लागतें वे पहलू हैं जिनपर इस संवर्धन नीति को संकेन्द्रण करना चाहिए।

1.77 सीमा शुल्क की क्रमिक रूप से कम होती दरों तथा उन्हें आसीयान देशों की दरों के साथ संरेखित करने की ओर संचलन जारी रहना चाहिए क्योंकि इससे भारतीय उद्योग को सहायता मिलेगी। पश्च-सुधार अनुभव स्पष्टतया दिखाते हैं कि कैसे एक खुली व्यापार प्रणाली प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा तथा उत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बेंचमार्किंग के बीच चक्रीय अंतः क्रिया के उपयोग में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त, अधिक लचीले श्रम कानून तथा सामान्य प्रतिस्पर्धी बाजार गतिकी के प्रत्युत्तर में फर्मों के सृजन तथा बंदी के दोहरे मुद्दों पर लोकप्रिय सहमति बनाना आवश्यक है। अंतिम किन्तु गौण नहीं, तीव्र औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि कम दरों तथा निविष्टि करों के लिए क्रेडिट व्यवस्था के साथ राज्य-स्तरीय मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली, की ओर परिगमन के लिए पहले से घोषित 1 अप्रैल 2005 की अन्तिम तिथि का पालन किया जाए। राज्य स्तर पर घरेलू व्यापार करों की वर्तमान व्यवस्था प्रपाती तथा बहुल दरों से उत्पन्न विकृतियों तथा अक्षमताओं से परिपूर्ण है।

1.78 बारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्त साधनों के सशक्तीकरण के मुद्दे की जांच भी शामिल है। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं, जिनके वर्ष के अंतिम भाग में प्राप्त होने की संभावना है, और साथ ही 2005-06 से मूल्य वर्धित कर की शुरुआत, राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार की महत्वपूर्ण निर्धारक होंगी।

1.79 राजकोषीय समायोजन में विनिर्दिष्ट उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कर तथा व्यय प्रशासन में सुधार बनाए रखने की आवश्यकता है। राजकोषीय समेकन के उद्घोषित लक्ष्यों के पीछे संकल्प के बारे में किसी भी विभ्रान्त संदेह को निर्भीक कार्यवाही द्वारा दूर किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने हेतु अधिक राजकोषीय गुंजायश का सृजन तथा वृहद्-आर्थिक स्थिरता के लिए सामाजिक नींव रखना राजकोषीय समेकन का पुरस्कार होंगे।